दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एक साथ प्रसारित

A UNIT OF VAANI ADVERTISING AGENCY

साप्ताहिक
खेत खजाना
खेत को खजाना बनाने का अभियान

RNI No. HARHIN11120
Postal Reg. No. : G/RNP/139/2018-20

वर्ष 2 अंक 16 सिरसा बुधवार 10 से 16 जुलाई, 2019 पृष्ठ 4 मूल्य : 8 रुपए e-mail : khetkhajana@gmail.com मो. 94160-11319

उत्तर भारत में अबके बंपर होगी कपास!

अबोहर। उत्तर भारत में नरमा कपास की फसल काफी अच्छी स्थिति में है और अभी तक किसी प्रकार के कीट या रोग के प्रकोप का कोई समाचार नहीं है। यह निष्कर्ष है पिछले दिनों यहां हुई

कृषि वैज्ञानिकों ने की समीक्षा बैठक

पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कृषि अधिकारियों, विभिन्न कृषि विवि के कृषि वैज्ञानिकों व केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई नरमा कपास फसल की समीक्षा बैठक का। इस बैठक में तीनों राज्यों के कृषि विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रही नरमा कपास की फसल की बढ़वार स्थिति पर चर्चा की और बताया कि तीनों राज्यों में सफेद मच्छर अथवा जूं का प्रकोप काफी कम है और अभी तक इस फसल पर किसी प्रकार के रसायनिक कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि अगर अगेती फसल में सफेद मच्छर की संख्या 4 से 6 प्रति पत्ता या जूं दस से बीस प्रति पत्ता मिलती है तो निंबीसीडिन एक लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। याद रहे कि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र सिरसा द्वारा सफेद मच्छर की प्रबंधन तकनीक में पहले से ही शेष पेज 3 पर...

सोना	34471
चांदी	38074
सेंसेक्स	38730.82
निफ्टी	11555.90
डॉलर	68.54

हरियाणा
सिरसा

गेहूं	1910
कपास	----
ग्वार	4095
सरसों	3600
चना	4080
जौ	1710

बासमती के निर्यात में जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली। भारतीय बासमती चावल के निर्यात से होने वाली आमदनी 2018-19 के दौरान 4.71 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। पिछले साल यह 3.20 अरब डॉलर थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार यह परिणाम सामने आया है। मंत्रालय का कहना है कि बासमती चावल के निर्यात की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा नहीं है और यह निरंतर जारी रहेगी। मंत्रालय का कहना है कि बासमती चावल के निर्यात में काफी बढ़ौतरी हुई है और यह अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी आगे बढ़ गई है। पिछले दिनों इस प्रकार की खबरें भी हवाओं में तैर रही थी कि अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंधों में चल रही खटास का बासमती चावल के निर्यात पर प्रभाव देखा जा सकता है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। शेष पेज 3 पर...

इफको द्वारा ग्रीन हाउस प्रबंधन किसान प्रशिक्षण सम्पन्न

इफको की ओर से पॉलि हाउस से सम्बंधित जानकारी बढाने हेतु 50 चयनित प्रगतिशील किसान भाईयों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 29-06-2019 को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक शनिवार को कृषि विभाग, आत्मा, सीकर के मीटिंग हाल में आयोजित किया गया। इसमें जयपुर से ग्रीन हाउस प्रबन्धन के विषय विशेषज्ञ राजेश सैनी ने कृषकों को ग्रीन हाउस में लगाए जाने वाली सब्जियों, कट फ्लावर की खेती एवं नर्सरी प्रबधन के गुर सिखाए। ग्रीन हाउस में क्लीमैटे कंट्रोल, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे विषयों पर परिचर्चा की। सीकर एवं झुंझुनूं जिले के 50 से ज्यादा प्रगति शील ग्रीन हाउस वाले कृषकों ने हिस्सा लिया। अजय गुप्ता, वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक, इफको, सीकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कृषि विभाग के एवं इफको के उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। इफको द्वारा प्रशिक्षण सामग्री के साथ वाटर सोलुब्ल फर्टिलाइजर एवं अपने प्रोडक्ट्स का किट वितरित किया गया। किसानों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई। प्रशिक्षण को लेकर किसानों में काफी जोश देखने को मिला। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कराये जाने की मांग की गई।

जैविक विविधता : थीम बेस्ड पार्कों का बढता चलन

अनेक प्रकार के पौधो एवं जंतुओ का अस्तित्व जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते है उसे जैविक विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाये जाने वाले समस्त सूक्ष्म जीव, पेड़-पौधे, वन्य जीव जन्तु एवं मनुष्य मिलकर जैविक विविधता की संरचना करते है। प्रकृति मे संतुलन बनाये रखने के लिए जैविक विविधता बेहद आवश्यक है। जैविक विविधता को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, परिस्थितिक विविधता, प्रजाति विविधता और आनुवशिकी विविधता।

बर्ड पार्क : इसका उद्देश्य देशी प्रजाति के पक्षियों को संरक्षित करना एवं विदेशी प्रजाति के पक्षियों को आकर्षित करना। ऐसे वृक्ष लगाना जो पक्षियों को आकर्षित करें। जिससे पक्षियों को खाना, रहने का स्थान एवं प्रजनन के लिए जगह इत्यादि प्रदान की जाती हो। गूलर, पीपल, अंजीर, पुतरंजीवा, देशी बबुल, बॉटल ब्रुश, बेर, शहतूत, लसोड़ा इत्यादि वृक्ष पक्षियों को आकर्षित करते हैं इस प्रकार के पार्क मे आर्द्रभूमि (वेट लैंड) एरिया अहम भूमिका निभाते हैं। बर्ड वाचरस घंटों पक्षियों को देखने के लिए रुकते हैं। बर्ड वाचर्स डायरी में पक्षियों की पहचान भी लिखी जाती है।

क्रम	ग्रहों के नाम	दिशा	ग्रहों का प्रतिनित्व करने वाले पौधों का नाम
1.	बुध	उत्तर पूर्व	(चिरचिटा या चिरचिरा)
2.	शुक्रा	पूर्व	(अंजीर या फिग)
3.	चन्द्रा	दक्षिण पूर्व	(पलाश या ढाक)
4.	गुरू	उत्तर	पीपल
5.	मंगल	दक्षिण	कादिरा
6.	सूर्या	मध्य	(सफेद आकड़ा)
7.	केतु	उत्तर पश्चिम	(शिरु या डाब)
8.	शनि	पश्चिम	शमी
9.	राहू	दक्षिण पश्चिम	दुब घास

बोटेनिकल पार्क, हावड़ा (कलकत्ता) काफी फेमस पार्क है। बोटेनिकल पार्क को भी हम कई हिस्सों मे बाँट सकते हैं जैसे रेगिस्तानी वनस्पतियों वाला बगीचा, ट्रॉपिकल कंजर्वेटरी गार्डन, लायजोर गार्डन, जलीय वनस्पतियों वाला बगीचा, आर्युवेदा गार्डन, बटरफ्लाइ गार्डन, नवग्रह गार्डन, नक्षेत्र गार्डन, ग्रीन हाउस गार्डन, बोंजाई गार्डन, नाइट गार्डन, टेरस गार्डन इत्यादि।

नवग्रह वाटिका का मतलब होता है 9 ग्रहों का बगीचा जिसमें प्रत्येक ग्रह के पौधे, घास, झाड़ियो एवं पेड़ों को एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। नवग्रह वाटिका में लगे हुए एक वृक्ष, पौधा, झाड़ी एवं घास किसी ना किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पक्षियों की पहचान एवं उनके संरक्षण के लिए समय-समय पर सेमिनार भी रखी जाती है।

लैंड स्केप पार्क : ऐसे पार्क लोगों एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे पार्कों मे योगा पवैलियन, विविंग डेक (मचान) ओपन एयर थैयटर, पनी का झरना, ऐरोबिक जोनएनदी का किनारा, फव्वारे, टॉपिएरी, लॉन, सुंदर डिजाइन किये हुए रास्ते, फूलों एवं गुलाब की क्यारियाँ भूल भुलईया, सिंचाई की नवीनतम तकनीक जैसे ड्रीप एवं पोप अप सिस्टम एवं विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियाँ लगाई जाती हैं। ऐसे पार्क सैर सपाटे एवं मौज मस्ती के लिए होते है।

बाटेनिकल पार्क : जैविक विविधता का जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप किसी भी बोटेनिकल पार्क चले जायें। बैंगलोर का लाल बाग बोटेनिकल पार्क एवं आचार्या जगदिश चन्द्र बोस इंडियन

नवग्रह वाटिका को लगाने का उद्देश्य :

1. इससे अच्छा स्वस्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
2. वास्तु दोष का निवारण होता है।
3. नौ ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से वास्तु को बचाता है।
4. दैवीय शक्तियों का इसमें वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
5. नवग्रह वाटिका जगह को तो सुंदर बनाती ही है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है।

बोटेनिकल पार्क, होटल, औधोगिक क्षेत्रों, बंगलो, फार्म हाउस, थीम बेसड पार्क में, टेरेस गार्डेन, इत्यादि जगह पर नवग्रह वाटिका लगाई जा सकती है ।

पार्क से होने वाले फायदे

1. शहरी एवं कस्बे क्षेत्रों के लोगों को प्रकृति की गोद में होने का अहसास कराता है। आज हमारे शहर कंकरीट के जंगल बनते जा रहे हैं ऐसे में पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। इसे बहतर बनाने के लिए पार्कों (बगीचों) की स्थापना करना बेहद जरूरी है।
2. पार्क मे जैविक विविधता पायी जाती है। एक ही स्थान पर विभिन्न प्रजातियों के जीव जन्तु एवं पेड़ पौधे पाये जाते हैं।
3. हमारे पार्क बच्चों एवं लोगों को वृक्षों के महत्त्व के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
4. शोध करने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त स्थान है हमारे पार्क। थीम बेस्ड पार्क में आपको हर तरह की वनस्पति देखने को प्रायः मिलती है जैसे रेगिस्तानी वनस्पतियां, जलीय वनस्पतियां, ट्रॉपिकल वनस्पतियां, औषधिय वनस्पतियां, देसी वनस्पतियां, विदेशी वनस्पतियां, विशेष प्रकार की प्रजातियाँ, आरबोरेटम इत्यादि।
5. जिन स्थानों पर पार्क स्थापित किए जाते हैं वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट अच्छा रहता है। लोगों को अच्छी वायु मिलती है। पार्क को अगर हम ऑक्सीजन चेम्बर भी कहें तो इसमें कोई आतिशीयोक्ति नहीं होगी। पार्क के आस-पास के लोग वहाँ सुबह-शाम भ्रमण कर सकते हैं।
6. आज के समय में उच्च या निम्न रक्तचाप, अवसाद, शुगर, मोटापा इत्यादि बीमारियाँ बढ़ रही हैं। अगर पार्क में रोजाना भ्रमण व्यायाम एवं योग इत्यादि किया जाए तो कारफी हद तक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। पार्क में लोग लाफ्टर थेरेपी का भी फायदा उठा सकते हैं।
7. पार्क मे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ लगा कर उनके बोटनिकल नाम प्रचलित नाम हिन्दी एवं इंगलिश नाम उत्पति स्थानय उपयोगिता इत्यादि के बोर्ड लगाए जा सकते हैं।

राजेश कुमार सैनी
उधान विशेषज्ञ

भारत सरकार द्वारा लाया गया कृषि बजट खेती के लिए निराशाजनक कागजों में आशावादी

बजट पर बयान जारी करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पेश किया गया कृषि बजट किसानों के लिए निराशाजनक व परेशानी भरा हुआ प्रतीत होता है बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थीं कि निर्मला सीतारमन द्वारा पिछ्ली सरकार में वाणिज्य मंत्री के रूप में व्यापार को आसान बनाने के लिए 7000 कदम उठाए गए थे। कृषि को आसान बनाने के लिए कम से कम 5000 कदम सुझाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यह बजट किसानों की आशाओं के विपरीत हैं एवं कागजों में आशावादी दिखाई देता है। बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है देश में किसानों को उम्मीद थी कि बजट में किसानों की आत्महत्याओं, फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद, मंडियों व भण्डारण की क्षमता को बढाना, कृषि ऋण को दीर्घकालिक व ब्याज मुक्त किए जाने के लिए सरकार कदम उठाएगी, सरकार ने बजट में इन मुद्दों को छुआ तक नहीं किसानों को समृद्ध बनाने हेतु सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु बजट शासकीय दस्तावेजों तक तो सही है लेकिन वास्तव में क्या? यह बजट देश को गुमराह करने वाला बजट साबित ना हो जाए ऐसे बजट से कृषि और किसान का कल्याण सम्भव नहीं है केवल सराहना और प्रतिबद्धता के आश्वासन पर खेती की चुनौतियों को कम किया जाना सम्भव नहीं है यह बजट गांव और किसान के हितों के विरूद्ध है बजट से किसानों में हताशा व निराशा का वातावरण वापस बन सकता है।

केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 प्रतिशत बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया है इसमें से 75,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना के लिए आवंटित की गई है सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में इसके लिए 77,752 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

आम चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत की गयी थी। इस योजना का लक्ष्य देश के 12.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये देना है। इसके अलावा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आबंटन को बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये करने का भी फैसला किया है और क्या वास्तव में फसल बीमा का लाभ किसानों तक पहुंच पाता है या केवल कागजों में खेलता हुआ केवल योजनाओं तक सीमित रह जाता है वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के मुताबिक इस योजना के लिए 12,975.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

करीब 5.61 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज सहायता के लिए 18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है बात यदि लघु ऋण की करें तो इसमें भी बैंकों की मनमानी चलती है और किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में इसके लिए 14,987 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी थी। कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए आबंटन को बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है इसी तरह, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) के लिए आबंटन को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है एमएसपी पर आज तक असमंजस है वाकई क्या होगा?

हालांकि, कृषि के मशीनीकरण के लिए बजट आवंटन में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। सरकार के इस वित्त वर्ष में इस मद में 600 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए सरकार ने बजट आबंटन को बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 3,500 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले के वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में यह आंकड़ा 2,954.69 करोड़ रुपया था। हरित क्रांति के तहत 18 केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए बजट आबंटन को बढ़ाकर 12,560 करोड़ रुपये कर दिया गया है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कृषि बजट से किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है प्रयास तो सार्थक किया गया है और वह क्या सकारात्मक रूप से लाभदायक साबित होगा यह एक प्रश्नचिन्ह लगाता है अतः मेरा विचार है यह बजट निराशावादी एवं कागजों में आशावादी ज्यादा नजर आता है।

पहली तिमाही में डीओसी का निर्यात 24 फीसदी घटा

आर एस राणा

नई दिल्ली। विश्व बाजार में भाव कम होने के कारण चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान डीओसी के निर्यात में 24 फीसदी की गिरावट आकर कुल निर्यात 5,71,325 टन का ही हुआ है। जून में इसके निर्यात में सबसे ज्यादा कमी 56 फीसदी की आई है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) के कार्यकारी निदेशक डॉ. बीवी मेहता ने बताया कि विश्व बाजार में भाव कम होने के कारण भारत से निर्यात में कमी आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दक्षिण कोरिया की आयात मांग तो 88 फीसदी ज्यादा रही, लेकिन वियतनाम और थाइलैंड की आयात मांग में क्रमशः 49.96 फीसदी और 42.27 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। ताईवान की मांग भी इस दौरान 6.81 फीसदी घटी है।

जून में निर्यात में में आई सबसे ज्यादा गिरावट

एसईए के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से जून के दौरान देश से केवल 5,71,325 टन डीओसी का ही निर्यात हुआ है जबकि पिछ्ले वित्त वर्ष 2018-19 की समान अवधि में 7,51,158 टन डीओसी का निर्यात हुआ था। जून महीने में डीओसी के निर्यात में सबसे ज्यादा 56 फीसदी की गिरावट आकर कुल निर्यात 1,14,972 टन का ही हुआ है जबकि पिछ्ले साल जून में इनका निर्यात 2,63,163 टन का हुआ था। जून में सोया डीओसी के साथ ही सरसों डीओसी और केस्टर डीओसी के निर्यात में भी कमी आई है।

सोया डीओसी के भाव घटे, सरसों और केस्टर डीओसी के बढ़े

सोया डीओसी का भाव भारतीय बंदरगाह पर जून में घटकर 445 डॉलर प्रति टन रह गया जबकि अप्रैल में इसका औसत भाव 460 डॉलर प्रति टन था। सरसों डीओसी का भाव अप्रैल के 220 डॉलर प्रति टन से बढ़कर जून में औसत भाव 221 डॉलर प्रति टन हो गया। केस्टर डीओसी का भाव अप्रैल के औसत भाव 77 डॉलर प्रति टन से बढ़कर जून में 109 डॉलर प्रति टन हो गया।

खेती के लिए भूजल स्तर में सुधार लाने की जरुरत पर जोर

आर एस राणा

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली आर्थिक समीक्षा 2018-19 में खेती के लिए भूजल स्तर पर में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय प्राथमिकता ष्भूमि की उत्पादकता से सिंचाई जल उत्पादकता की तरफ जाने की होनी चाहिए। नीतियों में सुधार करते हुए किसानों को इसके लिए संवेदनशील बनाना होगा और जल के इस्तेमाल में सुधार राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए विकास दर 2.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा में 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 28.34 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश करते हुए कहा कि जलस्तर में लगातार आ रही गिरावट खेती के लिहाज से खतरनाक है। एशियन वाटर डेवलेपमेंट के मुताबिक, करीब 89 फीसदी भू-जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई के मौजूदा चलन की वजह से भू-जल निरंतर नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है।

सिंचाई के लिए होता है 89 फीसदी भू-जल का इस्तेमाल

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सिंचाई के लिए 89 फीसदी भू-जल का इस्तेमाल किया जाता है। देश में धान और गन्ना की फसल उपलब्ध जल का 60 फीसदी से अधिक उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, जिससे अन्य फसलों के लिए कम पानी उपलब्ध रहता है। पिछ्ले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उभर कर सामने आई हैं।

जोत छोटी होने के साथ ही जल संसाधनों की कमी

इसमें कहा गया है कि कृषि भूमि के बंटवारे और जल संसाधनों के कम होने से संकट बढ़ा है। अपनाये गये नये प्रभावी संसाधनों और जलवायु के अनुकूल सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र स्मार्ट हुआ है। कृषि जोतों के छोटा होने की वजह से भारत ने सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार किसानों को पानी के उपयोग के कुशल तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों को तैयार करना होगाए साथ ही जल संकट को कम करने की राष्ट्रीय प्राथमिकता बनानी चाहिए।

जून में बारिश सामान्य से 33 फीसदी कम हुई

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है। हालांकि, जून के दौरान मानसूनी बारिश सामान्य से 33 फीसदी कम हुई थी जिस कारण खरीफ फसलों की बुआई में कमी आई है। आईएमडी ने कहा है कि जुलाई और अगस्त में बारिश अच्छी होने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में वर्ष 2013-14 में 17.7 फीसदी की बढ़त दिखायी देती है, लेकिन इसके बाद वर्ष 2017-18 में यह घटकर 15.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 के सकल पूंजी निर्माण 2,51,904 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में यह 2,73,555 करोड़ हो गई।

कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, महिलाएं फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, कटाई के बाद के कार्यकलाप कृषि/सामाजिक, वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं द्वारा उपयोग में लायी जा रही क्रियाशील जोतों का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 11.7 फीसदी से बढ़कर 2015-16 में 13.9 फीसदी हो गई। महिला किसानों द्वारा संचालित सीमांत एवं छोटी जोतों का अंश बढ़कर 27.9 फीसदी हो गया है।

जूनोटिक रोगों से बचाव में वेटरनरी डॉक्टर का रोल ज्यादा अहम

डॉ. योगेश आर्य वैटरीनेरियन

(संदर्भ : विश्व जूनोसिस दिवस)

शनिवार 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस होता है। ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना है। मोटे तौर पर समझा जाये तो जूनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। जब ये रोग मनुष्यों से जानवरों में फैलते है तो इसे रिवर्स जूनोसिस कहा जाता हैं। जूनोटिक रोग बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद अथवा परजीवी किसी भी रोगकारक से हो सकते हैं। भारत मे होने वाले जूनोटिक रोगों में रेबीज, ब्रूसेलोसिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ईबोला, निपाह, ग्लैंडर्स, साल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस एवम जापानीज इन्सेफेलाइटिस इत्यादि शामिल हैं। ये लिस्ट काफी लम्बी हैं, विश्व भर में लगभग 150 जूनोटिक रोग उपस्थित हैं। कुछ जूनोटिक रोग तो सीधे ही सम्पर्क में आने से फैलते हैं जबकि कुछ वेक्टर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, घोंघा, चिचड़, मछली, सुवर, मुर्गी और घोड़ा इत्यादि के द्वारा फैलाये जाते हैं। हमारी आधी-अधूरी तैयारियों के कारण भविष्य में जूनोटिक रोगों के रूप में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा हैं। जूनोटिक रोगों से बचाव में वेटरनरी डॉक्टर मुख्य रोल अदा करता हैं। पालतू और जंगली दोनों प्रकार के जानवरों में लक्षणों को पहचान कर तुरंत प्रभावी उपाय किये जाने में वेटरनरी डॉक्टर अहम कड़ी हैं। कुछ जूनोटिक रोगों को तो टीकाकरण करके रोका जा सकता हैं बाकी की समय पर पहचान करके बचाव हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर रोगों की पहचान में वेटरनरी पैथोलोजिस्ट मददगार होते हैं। रेबीज और ब्रूसेलोसिस जैसे रोगों से बचाव के लिए तो टीकाकरण एक उपयुक्त माध्यम हैं ही। अबकी बार विश्व पशुचिकित्सा दिवस पर भी थीम टीकाकरण का महत्व ही रखी गयी थी। जूनोटिक रोगों से बचाव की तैयारियों पर अगर जाएं तो आग लगने पर कुवां खोदने जैसी हालत हैं। वेटरनरी प्रोफेशन बजट और सुविधाओं के नाम पर इस वक्त दयनीय हालात में हैं। इस बार केंद्र सरकार ने पशुपालन के लिए अलग से मंत्रालय और विभाग बनाया हैं जिससे जरूर उम्मीद जगी हैं। साथ ही आईसीएआर की तर्ज पर वेटरनरी रिसर्च कॉउंसिल भी बनेगी। ऐसा होने पर निश्चित तौर पर वेटरनरी प्रोफेशन अधिक दक्षता से जूनोटिक रोगों से लड़ाई में शामिल हो पायेगा। ऐसा होने में वक्त लगेगा पर अभी पशुचिकित्सा सेवाओं में काफी सुधार की दरकार हैं। इनकी आवश्यकता हर जगह है फिर चाहे वो जूनोटिक रोगों से बचाव हो, शुद्ध और अधिक दूध उत्पादन हो या फिर गुणवत्तापूर्ण मांस और अंडा उत्पादन। अब जूनोटिक रोगों से इतर थोड़ी चर्चा पशुचिकित्सा व्यवस्थाओं और पशुपालन के हालातों पर भी कर लेते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राज्य का 5.77 करोड़ पशुधन एक सम्पदा की तरह हैं। राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद में पशुधन सम्पदा का 10 प्रतिशत योगदान है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अन्य पशु उत्पादों की बात करे तो राज्य का देश में ऊन उत्पादन में पहला और मांस उत्पादन में बारहवां स्थान है। सरकार पशुपालन व्यवस्थाओ को सुदृढ़ बनाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। परंतु चिंताजनक बात हैं कि हर बार पशुगणना में पशुधन कि संख्या कम ही होती जा रही हैं। वर्तमान में राज्य की पशुचिकित्सा व्यवस्थाओ की हालत भी अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार प्रति 5 हजार पशुओं पर एक वेटरनरी डॉक्टर होना चाहिए, इस गणना के हिसाब से राज्य में लगभग 12 हजार वेटरनरी डॉक्टर्स होने चाहिए, जबकी हकीकत ये है कि 60 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं। तमाम पशुचिकित्सा व्यवस्थायें नीम-हकीमों के हवाले हैं, हॉर्मोन के अनाधिकृत उपयोग से पशुओं में बाँझपन बढ़ रहा हैं। अनधिकृत उपयोग के कारण एंटीबायोटिक्स अप्रभावी होती जा रही हैं जो कि पूरी खाद्य श्रृंखला के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में वेटरनरी डॉक्टर्स के ऊपर अधिक जिम्मेदारी होती हैं कि वो तय मानकों के अनुसार ही पशु उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। कृषि एवं पशुपालन राज्य का विषय होता है, अतः राज्य सरकार को पशुचिकित्सा तकनिकी शिक्षा को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। वेटरनरी में उच्च शिक्षा और रिसर्च को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वेटरनरी शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना अधिक आवश्यक हैं क्योंकि देशी पशु नस्ल की संख्या लगातार कम होती जा रही हैं। देशी नस्लों के पशु राजस्थान के वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं, बीमार भी कम पड़ते है और अकाल के समय बेरी-पाला और खेजड़ी की पत्तियों पर भी गुजारा कर लेते है। देशी गायें, 2 प्रकार का दुग्ध देती हैं, जोकि सुपाच्य और पोष्टिक होता है। राजस्थान सरकार ने गोपालन विभाग की स्थापना तो कर दी परंतु वो अभी तक कागजों से बाहर निकल कर यथार्थ रूप नही ले पाया हैं और पशुपालन विभाग पर ही आश्रित है। सरकार द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास किये जाने चाहिए। उन्नत नस्लों के पशुओं के पालन पर जोर दिया जाना चाहिए। गायों में चयन और उन्नयन पद्धतियों से दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि होना निश्चित हैं। पशुपालन व्यवसाय में बढती लागत तथा दुग्ध उत्पादन में बढोतरी नहीं होने से छोटे किसानो का पशुपालन के प्रति रुझान घट सकता है। इसलिए युवा पशुपालकों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, नवीन अनुसंधानों के प्रयोग से अधिक दुध उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। पशुचिकित्सा सेवाओं, और लाभकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी आवश्यक हैं। अभी भी ग्रामीण इलाकों में पशुओं और पशुपालकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उतनी जागृति दिखाई नहीं देती है। पशुपालकों को अभी भी समय पर कृमिनाशन, टीकाकरण करवाने के फायदे नहीं पता हैं। पशुपालन विभाग जब भी टीकाकरण अभियान चलाता हैं तो उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। पशुपालकों को अभी भी कृत्रिम गर्भाधान के लाभ और अवर्गीकृत नस्लों के नकारा नर पशुओं के बधियाकरण करवाने के लिए जागृत करने की जरूरत हैं। दूर-दराज के इलाकों मे पशुओं का इलाज सिर्फ झाड़-फूंक से ड़ाव लगाकर किया जा रहा हैं। इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष और अधिक पशुचिकित्सा विशेषज्ञों की दरकार हैं। अतः सरकार पशुचिकित्सा सेवाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेंद्य डेयरी स्थापित करने के लिए पशुपालकों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए। पशुओं के बीमा करवाने की प्रीमियम दरें कम करें। देशी नस्लों के पालन को प्रोत्साहित करें। उत्तम नस्ल के नर पशु ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाएं ताकि नस्ल सुधार किया जा सके। गौशालाओं की हालत सुधारें और सबसे बड़ी बात ये कि पशुचिकित्सा प्रोफेसनल्स कि भर्ती करें ताकि ना केवल पशुधन को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके बल्कि पशुधन उत्पादन में वृद्धि हो सके। जूनोटिक रोगों से बचाव में वेटरनरी डॉक्टर्स के रोल का ताजा उदाहरण राजस्थान में ग्लेंडर्स के केस मिलने पर सामने आया। पशुपालन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए स्क्रीनिंग में संदेहास्पद पाए मामलों के सैम्पल प्रयोगशाला में भेजें। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर घोड़ो-खच्चरों का यूथेनेशिया दिया गया। पशुमेलों में घोड़ो के इकट्ठा होने से रोकने के लिए घोड़े लाने पर रोक लगा दी गयी। पालतू पशुओं की बात तो हो गयी परंतु जंगली जानवरों पर तो सर्वाधिक संकट है। घटते वनों से जंगली जानवरों के रहने और खाने-पीने की समस्या खड़ी हो गयी हैं। फिर दूसरा पहलू ये कि उनकी चिकित्सा व्यवस्थाएं भी ज्यादा अच्छी नही हैं। उनसे होने वाले जूनोटिक रोगों से भी काफी बार जूझना पड़ता है। इस बीच बड़ा बिंदु ये भी हैं कि जूनोटिक रोगों से बचाव हेतु वेटरनरी और मेडिकल दोनों प्रोफेशन में बेहतर तालमेल बहुत जरूरी हैं, प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए। जूनोटिक रोगों से लड़ाई की सभी योजनाओं और प्रयासो में वेटरनरी डॉक्टर्स को शामिल किया जाना चाहिए।

खरीफ फसलों की बुआई में आई कमी से सरकार चिंतित, राज्यों के संपर्क में

आर एस राणा

नई दिल्ली। चालू खरीफ सीजन में मानसूनी बारिश कम होने के कारण फसलों की बुआई में आई कमी पर सरकार ने चिंता जताई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ फसलों की बुआई में अभी समय बचा है, लेकिन सरकार किसी भी स्थिति से निपेटने के लिए राज्यों के सपंर्क में है।

उन्होंने कहा कि सूखे जैसी स्थिति से संयुक्त प्रयासों से निपटने को केंद्र राज्यों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की बुआई में देरी चिंता का विषय तो है लेकिन किसानों के पास बुआई पूरी करने के लिए अभी समय बचा हुआ है।

आईएमडी ने जुलाई-अगस्त में जताया अच्छी बारिश का अनुमान मौजूदा खरीफ सत्र 2019-20 में पिछले सप्ताह तक खरीफ बुआई एक साल पहले की तुलना में 27 फीसदी पिछड़ कर 234.33 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंची थी जबकि पिछले साल की समान अवधि में 319.68 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। तोमर ने कहा कि सूखे जैसी स्थिति को लेकर हम राज्यों के संपर्क में हैं। खरीफ फसल की उपज के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा कि अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है जिससे बुआई के काम में तेजी आ सकती है।

चालू खरीफ में अभी तक 17 फीसदी बारिश सामान्य से कम दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ खरीफ फसल की बुआई शुरू होती है। इस साल इसमें देरी हुई जिससे बुआई भी पीछे चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून में देशभर में मानसूनी बारिश सामान्य से 33 फीसदी कम हुई थी जबकि पहली जून से 9 जुलाई तक देशभर में 17 फीसदी बारिश सामान्य से कम हुई है। खरीफ की मुख्य फसल धान की बुआई पिछले सप्ताह तक 52.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी, जो एक साल पहले की समान अवधि 68.60 लाख हेक्टेयर कम है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में धान की बुआई पीछे चल रही है।

दलहन के साथ मोटे अनाजों की बुआई भी कम : इसी तरह दलहनों अरहर, उड़द और मूंग की बुआई अभी तक सिर्फ 7.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 27.91 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाजों की बुआई भी पिछले साल के 50.65 लाख हेक्टेयर से घटकर 37.37 लाख हेक्टेयर रह गई है।

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 15 तक करवाएं रजिस्ट्रेशन

सिरसा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 को अधिसूचित करते हुए चालू सत्र खरीफ 2019 की चार फसलों कपास, धान, बाजरा व मक्का के प्रति हैक्टेयर प्रीमियम एवं बीमित राशि की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के तहत आगामी 15 जुलाई 2019 तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है।

यह जानकारी देते हुए कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. बाबूलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2019 सीजन में फसलों के बीमा के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा जिला के गांवों में के पों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन केंपों का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग योजना से जुड़ें और इनका लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार धान फसल का प्रीमियम 1556 रुपए प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कपास फसल हेतू प्रीमियम राशि 1532 रुपए प्रति हैक्टेयर, बाजरा फसल के लिए प्रीमियम राशि 740 रुपए तथा मक्का फसल हेतू प्रीमियम राशि 776 रुपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम किसानों से लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैकों द्वारा सभी ऋणी किसानों की फसलों का बीमा किया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी ऋणी किसान 15 जुलाई तक अपने बैंक जहां से के.सी.सी. लिया गया है उसमें बोई गई सही फसल की जानकारी उपलब्ध करवांए ताकि किसानों द्वारा बोई गई फसलों का ही बीमा किया जा सके। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपना आधार न बर भी बैंक खातों से लिंक करवा लें। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान किसी भी सीएससी केन्द्र पर जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।

पेज एक के शेष

उत्तर भारत में...

नीम आधारित दवाओं का छिड़काव करने की सिफारिश की हुई है। बैठक में हरियाणा से जुड़े कृषि विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि सरसों की फसल के बाद जिन खेतों में नरमा कपास की बिजाई हुई है उनमें डस्की कॉटन बग नामक काले कीट का प्रकोप देखा गया है जिसमें फूल डोडी नीचे गिर रही है। इस अवस्था में भी नीम आधारित दवाओं का छिड़काव करने की सलाह दी गई है।

बासमती के निर्यात...

उल्लेखनीय है कि अमेरिका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात सहित कई बड़े देश भारत से बासमती चावल सहित अन्य कृषि उत्पाद आयात करते हैं और ईरान इसका सबसे बड़ा खरीददार है। खेत खजाना ने अपने पिछले अंकों में स्पष्ट किया है कि ईरान को निर्यात होने वाले बासमती चावल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है बल्कि आगामी एक डेढ़ साल तक भी इस बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव आने की संभावना नहीं है।

लोगों की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट : चौपड़ा

सिरसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक मई को पेश किया गया बजट लोगों की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। व्यापक रूप से जनहितैषी बजट में हर वर्ग का याल रखा गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को ग्रीन बजट का नाम दिया है।

> **सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट पेश करके एक मिसाल कायम की है।**

यह बात हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने आज बजट पर चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम बजट में वित्त मंत्री निर्मलाा सीतारमण ने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट पेश करके एक मिसाल कायम की है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह बजट व्यापक जनहित का बजट है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में आम आदमी से लेकर किसान, व्यापारी, महिला व युवा सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। रोजगार की दृष्टि से भी बजट आमजन की आशाओं के अनुरुप है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के अभूतपूर्व विकास विशेषकर महिलाओं के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगा। यह बजट देश के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। श्री चौपड़ा ने कहा कि बजट गरीब वर्ग के उत्थान की दिशा में लागू विभिन्न परियोजनाओं के गतिमान बनाए रखने के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी आवश्यक वस्तुएं जोकि आम लोगों की रोजमर्रा का हिस्सा हैं, इस बजट के बाद सस्ती होंगी, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। बजट में रोजगार की दिशा में सुदृढता लाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक का याल बजट में रखा गया है।

उन्होंने महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निर्मला जी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आधुनिक तो है लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को भूला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।

देशी बीजों को बचाने के लिए कार्य कर रहा है समृद्धि देशी बीज बैंक

रुठियाई। अपनी प्राइवेट नौकरी के साथ-साथ देशी बीजों को बचाने, उनके संवर्द्धन और प्रचार प्रसार में जुटे केदार सैनी समृद्धि देशी बीज बैंक रुठियाई के माध्यम से देशभर के किसानों, देशी बीजों के सरंक्षण संवर्द्धन से जुड़े धीर गंभीर लोगों को न सिर्फ बीज मुहैया करवा रहे हैं बल्कि इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।

वे बताते हैं, देशी बीजों से जुड़ी जानकारियों और उनकी तलाश के चलते कई जगह से मेरे पास फोन आते रहते हैं। ज्यादातर लोग देशी बीजों की मांग करते हैं। परंतु यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि पर्याप्त मात्रा में यह अब उपलब्ध नहीं हैं। अब भी समय है, यदि हम समय रहते चेत गए तो देशी बीजों की मांग को देशभर में पूरा कर पाएंगे। देश में कृषि के लिए बीजों की कमी है, इसका फायदा विदेशी कंपनियां उठा रही हैं, ऊंचे दामों पर किसानों को हाइब्रिड बीज परोस रही हैं।

अब आगे क्या? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, इसी अनुपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए देशी बीजों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में देशी बीजों के उत्पादन पर विचार कर रहे हैं, जिसके चलते देशी बीजों की दिनों दिन बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

समृद्धि देशी बीज बैंक रुठियाई ने जैविक खेती करने वाले भारतीय किसानों को इन देशी बीजों के सरंक्षण संवर्द्धन के लिए न सिर्फ प्रेरित किया है बल्कि अब तो दुबई और नेपाल जैसे बाहरी मुल्कों से भी देशी बीजों के संरक्षण संवर्द्धन के लिए प्रेरित किया जिसके सुखद परिणाम अब आने लगे हैं।

समृद्धि देशी बीज बैंक रुठियाई द्वारा अधिकाधिक मात्रा में देशी बीजों के उत्पादन के लिए मध्यप्रदेश के चार जिलों गुना, राजगढ़, इंदौर और खरगोन से 4 किसानों का चयन किया गया है, इस बैंक के लिए बीजोत्पादन का कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए उधम सिंह लोधा, विजय कुमार विश्वकर्मा, दीपक कुमार पटेल और अविनाश दांगी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समृद्धि देशी बीज बैंक रुठियाई के संयोजक केदार सैनी से जुड़कर उनकी मुहिम को बल दें।

मोबाइल 078989-15683

> **केदार सैनी और उनके सहयोगियों द्वारा देशी बीजों के सरंक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। आज के इस दौर में हमें हमारी जड़ों को बचाकर रखने की सख्त जरूरत है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हर संभव मदद के लिए भी तैयार हूं।**
> **–राकेश चौधरी,** प्रगतिशील किसान एवं सदस्य, राष्ट्रीय औषध पादप मंडल, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

मानसून 2019 : इफको किसान एवं अपोलो टायर्स ने साथ में शुरू की किसानों के लिए सलाहकार सेवाएँ

भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत कृषि प्रधान देश होने की वजह से मानसून पर काफी निर्भर करता है। लेकिन कई दशकों से भारतीय कृषि असमान्य मानसून का शिकार बनती जा रही है।

खरीफ मौसम में धान, मक्का, कपास और दालों जैसी नई फसलों की खेती की जाती है। इस साल मानसून की धीमी शुरुआत किसानों और पूरे देश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

अपनी धीमी शुरुआत के साथ, पिछले कुछ दिनों में मानसून ने गति पकड़ी है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल है। हालांकि, मानसून की शुरुआत में लगभग एक सप्ताह की देरी के कारण, खरीफ फसलों की बुवाई में 27 प्रतिशत की कमी आई है।

भारत में बदलती जलवायु परिस्थितियों और अल नीनो प्रभाव के कारण सामान्य मानसून प्रभावित होता जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। वर्षों से लगातार असमान्य बारिश के कारण, देश के कुछ हिस्सों में मानसून में कमी की संभावना इस साल भी बताई जा रही है, जो किसानों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जुलाई में मानसून की कमी और मानसून 2019 में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की है। प्री-मानसून सीजन में भी बारिश की कमी दर्ज की गई थी। इस बीच, स्काईनेट ने अल नीनो और बारिश की कमी की संभावना का हवाला देते हुए औसत से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। यह कृषि क्षेत्र के लिए चिंतित होने का एक कारण है क्योंकि इससे दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली खरीफ फसलों का फसल चक्र प्रभावित होगा। मानसून 2019 कृषि संकट को बढ़ा सकता है क्योंकि खरीफ की फसलें बारिश के समय और वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है।

जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में फसल उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। अनिश्चित मानसून के साथ, अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की 50 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। आमतौर पर छोटे और सीमांत किसान अनियमित मानसून के शिकार बन जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अपोलो टायर्स ने इफको किसान के साथ मिलकर मानसून के इस मौसम में कॉल, एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं पहुंचने की शुरूवात की हैं, ताकि वे फसल के नुकसान से बच सकें।

इफको किसान के सीईओ श्री संदीप मल्होत्रा ने कहा, हम पिछले एक दशक से किसानों के लिए कृषि एवं इसके सुधारात्मक उपायों के लिए काम कर रहे हैं। अपनी इस नई पहल में, हमने अपोलो टायर्स के साथ मिलकर मौसम के अपडेट और किसानों के लिए मानसून टिप्स के नाम से सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं। हम कृषक समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहते हैं और किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं।

दूसरी ओर, इफको किसान मोबाइल ऐप बारिश की संभावना एवं अपेक्षित हवा की गति जैसी मौसम पूर्वानुमान से संबन्धित जानकारी किसानों तक पहुंचाती रही है। यह किसानों को कृषि और खेती से संबंधित गतिविधियों के लिए सुधारात्मक उपाय एवं विशेषज्ञ सलाह प्रदान करती आ रही है। इफको किसान मोबाइल ऐप में विशेषज्ञ से पूछें एक विकल्प है जिसके माध्यम से किसान अपनी समस्याओं को लिखकर एवं बोलकर, यहां तक की अपनी समस्याओं की तस्वीरें भी भेज सकते हैं और दर्ज करवा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्याओं का हल उनकी ही भाषा में ऐप पर ही दिया जाता है।

अपोलो टायर्स के श्रेणी प्रमुख श्री फरीद अहमद ने कहा, कृषि उद्योग में मानसून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कृषक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए हमने इफको किसान के साथ मिलकर जिला/ब्लॉक स्तर पर सलाहकार सेवाओं की व्यापक रेंज और सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को मानसून के सुझाव देने की शुरुआत की है। हम फार्म टायरों की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करते हैं जो कीचड़ और गीली मिट्टी में पकड़ के लिए अनुकूल है, और मानसून के मौसम में किसानों के लिए लाभदायक है। मानसून किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह मौसम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वार्षिक वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत इस मौसम में ही देखा जा सकता है। जो जुलाई से सितंबर तक है। भारत का बारिश के मामले में कुछ खास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्योंकि देश पिछले कई वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। इसलिए इस मानसून में अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। किसान समुदायों, कॉर्पोरेट्स एवं पूरी देश की जनता को जल और पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में पहल करनी होगी, इसी पहल के अंतर्गत इफको किसान एवं अपोलो टायर्स ने मिलकर किसानों के लिए ये शुरुआत की है।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी से धान किसानों की लागत बढ़ी

नई दिल्ली। जुलाई का पहला सप्ताह बीतने के बावजूद भी उत्तर भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश कम होने से धान किसानों को ट्यूबवैलों से रोपाई करनी पड़ रही है जिससे उनकी लागत बढ़ गई है। पहली जून से 7 जुलाई तक हरियाणा में मानसूनी बारिश सामान्य से 55 फीसदी, पंजाब में 50 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 42 फीसदी कम हुई है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है लेकिन इन राज्यों में चालू सीजन में मानसूनी बारिश अभी तक सामान्य से कम हुई है। पंजाब में पहली जून से 7 जुलाई तक सामान्यतः 80 मिलीमीटर बारिश होती है जबकि चालू सीजन में अभी तक केवल 40.2 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, इसी तरह से हरियाणा में इस दौरान 70.6 मिलीमीटर बारिश होती है जबकि अभी तक हुई है केवल 31.4 मिलीमीटर ही। इसी तरह से चालू मानसूनी सीजन में उत्तर प्रदेश में पहली जून से 7 जुलाई तक 80 मिलीमीटर बारिश ही हुई है जबकि सामान्य इस दौरान राज्य में 138.5 मिलीमीटर बारिश होती है।

बारिश नहीं होने से ट्यूबवैल चलाकर कर रहे हैं किसान धान की रोपाई

हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना के किसान राजेश कुमार ने बताया कि जून के अंत तक बारिश हो जाती है, जिससे धान की रोपाई भी शुरू हो जाती है लेकिन इस बार जुलाई का पहला सप्ताह बीच चुका है लेकिन बारिश नहीं हुई है। पांच एकड़ में पूसा-1121 की रोपाई के लिए धान की पौध तैयार कर रखी है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण अभी तक ट्यूबवैल से दो एकड़ में ही रोपाई की है। धान के खेत में पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए ट्यूबवैल लगातार चलाना पड़ रहा है, जिससे डीजल खर्च बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के किसान जोगिंद्र आर्य ने बताया कि अभी बारिश नाममात्र की ही हुई है जबकि धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है ऐसे में बारिश नहीं के कारण ट्यूबवैल से सिंचाई कर रोपाई की जा रही है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रोपाई पिछड़ी

कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में हरियाणा में धान की रोपाई अभी तक केवल 2.51 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है जबकि पिछले साल इस समय तक 4.71 लाख हेक्टेयर में रोपाई हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में भी चालू सीजन में धान की रोपाई 3.15 लाख हेक्टेयर में ही हुई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 7.10 हेक्टेयर में हो चुकी थी। पंजाब में जरुर चालू सीजन में धान की रोपाई बढ़कर 21.07 लाख हेक्टेयर में हुई है जोकि पिछले साल की समान अवधि के 19.06 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मुक्ता द्वारा परोपकार प्रिंटिंग प्रेस, सातवां मील, भादरा रोड सिरसा से मुद्रित एवं पुरानी चुंगी बेगू रोड सिरसा से प्रकाशित। संपादक लाजपुष्प। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सिरसा न्यायालय होगा। RNI No. HARHIN11120